(v) STARVATION AMONG ADIVASI MINERS DUE TO LOCK-OUT IN KIRIBURU QUARTZITE MINES OF SINGHBHUM DISTRICT OF BIHAR

श्री रामवतार शास्त्री : (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय बिहार के सिंहभूम जिले के अन्तर्गत लोटा पहाड़ में किरोदुरू क्वार्टजाइट खनिज खदानों में पिछले दो साल से भी अधिक दिनों से गैर कानूनी तालाबन्दी चल रहा है। इसके फलस्वरूप दो हजार आदिवासी खनिकों तथा उनके दस हजार आश्रितों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है । इन खनिकों में डेढ़ हजार आदिवासी लड़कियां भी हैं, जिन्हें जिन्दा रहने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के भट्टा उद्योग में तरह-तरह की अमानवीय यातनायें बर्दास्त करनी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, भट्टों के ठेकेदारों के जाल में फंस कर उन्हें अपनी इज्जत आबरू बेचने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है ।

सरकार का दावा है कि उसने बंधवा मजदूरी प्रथा का अन्त कर दिया । परन्तु यह बात सच्चाई से कोसों दूर है । अगर किन्हीं को बन्धवा मजदूर की तरह खटते हुए आदिवासियों को देखना हो तो वे पश्चिम बंगाल के बारासात-मगरा और बंडेल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वाराणसी और गोरखपुर तथा उत्तर बिहार में ईट के भट्टों में जाकर देख लें। उनकी आंखें खुल जायेंगी । उक्त स्थानों पर आदिवासी लडकियों को होटलों में अनैतिक कार्य के लिए बेचा जाता है। इस प्रकार की तमाम आदिवासी लड़कियां किरोबुरू खदानों को बेकार कामिन है।

किरोबुरू क्वार्टजाइट खनिजों में उच्च कोटि की सिलिका होती है जिस का उपयोग इस्पात उद्योग के कोक-ओवन में होता है । देश में इस्पात उद्योग में वृद्धि के साथ-साथ सिलिका ब्रिक्स की मांग प्रत्येक साल बढ़ती जा रही है । इसलिए यह देश के हित में है कि भारत रिफैक्टरी लि०, किरोबुरू की क्वार्टजाइट खदानों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें अविलम्ब चालू करे ताकि बेकार आदिवासी मजदूरों को काम मिल जाये जिसका सहारा लेकर वे अपने परिवार के लोगों का भरण-पोषण कर सकें ।

भारत सरकार के खान एवं श्रम मंत्रियों से मेरा अनुरोध होगा कि वे इसमें शीघ्र हस्तक्षेप कर बन्द खदानों को खुलवाने में पेशकदमी लें ।

(vi) NEED FOR INCLUSION OF GAWADA, KUMBI, VELPI AND DHANGAR COMMUNITIES OF GOA AMONG THE SCHEDULED TRIBES

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Sir, the Gawada, Kumbi, Velpi and Dhangar communities in Goa represent about 2 lakh people and account for about one fifth of the total population of that Union Territory. They have a common tribal culture and are historically the original settlers of this part of the coast. Yet, they constitute the most backward section of the population there. The Commissioner for Scheduled Castes and Backward Tribes in his report for the year 1964—66 had recommended that these communities be included among the Scheduled Tribes.

Since then several representations were made by the leaders of these communities and others interested in their welfare for their inclusion among the Scheduled Tribes but without any practical result. Recently during the vist of the Backward Classes Commission under the Chairmanship of Shri B. P. Mandal to that territory, the case for the inclusion of these communities among the Scheduled Tribes was once again made and the Commission reacted very favour-